+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(08 July 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारत-रूस सम्बन्ध: प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस जाने का महत्व
- डिजिटल भारत निधि (DBN)
- MCQ

भारत-रूस सम्बन्ध: प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस जाने का महत्व

चर्चा में क्यों हैं?

- लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रूस जा रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दोनों नेताओं की कुल 16 बार मुलाकात हुई है, लेकिन फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है।
- प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के लिए रूस गए थे; राष्ट्रपति पुतिन पिछली बार दिसंबर 2021 में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे।

इस यात्रा का क्या महत्व है?

- प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ने कई कारणों से दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है इसका समय। आमतौर पर, भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महीनों पहले सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध

और समन्वित किए जाते हैं। वे वर्ष के अंत में होते थे। लेकिन वर्तमान यात्रा की घोषणा आखिरी समय में की गई।

- दूसरा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, यह द्विपक्षीय उद्देश्यों के लिए किसी विदेशी देश की उनकी पहली यात्रा होगी। पिछले महीने उनकी इटली यात्रा बहुपक्षीय उद्देश्यों यानी जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए थी। तीसरा, पीएम मोदी की रूस यात्रा वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाती है। और अंत में, कुछ दिन पहले ही, प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान में एससीओ बैठक को छोड़ दिया था।इन घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के समय और तात्कालिकता के बारे में कई अटकलें लगाई जाने लगीं।

रूस के संबंधों की प्राथमिकता को रेखांकित करना:

- विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की हाल की रूस यात्रा रूस को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि दोनों देशों के बीच संबंध बरकरार हैं और भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। क्योंकि पिछले कुछ समय से, खासकर रूसी पक्ष की ओर से, इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। रूस में नीति निर्माताओं को संदेह था कि ऐसा अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है।

- उल्लेखनीय है कि शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नए प्रधानमंत्री द्वारा पहले किसी पड़ोसी देश की यात्रा करने की परंपरा को तोड़ दिया है, जिसका उन्होंने जून 2014 (भूटान) और जून 2019 (मालदीव और श्रीलंका) में भी पालन किया था।
- रूस की यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है और विदेश नीति में इस प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है?

- रूस के साथ भारत के संबंध बहुत व्यापक हैं। वैश्विक राजनीति में ऐसा कोई समानांतर नहीं है। वर्ष 2000 में, उन्होंने रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2010 में "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया। तथ्य यह है कि उनके पास एक वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन तंत्र है जो दोनों देशों के बीच सहयोग के स्तर को दर्शाता है। यह एक संस्थागत साझेदारी है।
- फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्षों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

बढ़ता व्यापार असंतुलन और भारतीय पक्ष से भुगतान का मुद्दा:

- पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में रूस के साथ भारत का व्यापार बढ़कर लगभग 65 अरब डॉलर हो गया। इसमें भारत का आयात लगभग 60 अरब डॉलर का था, जबकि निर्यात मात्र 4 अरब डॉलर था। ऐसे दोनों पक्षों के बीच व्यापार असंतुलन बहुत बड़ा है। इस असंतुलन को कम करने के लिए रूस को भारत से अधिक उत्पाद खरीदने चाहिए।
- इसके अलावा, रूस डॉलर, यूरो या रेनमिनबी जैसी कठोर मुद्राओं में भुगतान पर जोर देता है, जबकि भारत भारत में निवेश करने और यहां से अधिक उत्पाद खरीदने पर जोर देता है।

भारत-रूस रक्षा साझेदारी:

- शीत युद्ध के दशकों के दौरान सोवियत संघ भारत के रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्तिकर्ता था, और अब भी, भारत के 60 से 70 प्रतिशत रक्षा उपकरण रूसी और सोवियत मूल के होने का अनुमान है। समय के साथ रक्षा सहयोग क्रेता-विक्रेता ढांचे से विकसित होकर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, सह-विकास और संयुक्त उत्पादन से जुड़ा हुआ हो गया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- भारत और रूस ने S-400 ट्रायम्फ मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, MiG-29 लड़ाकू विमान और कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति और T-90 टैंक, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, AK-203 असॉल्ट राइफल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना के दो विमानवाहक पोतों में से एक INS विक्रमादित्य पूर्व सोवियत और रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव है।
- पिछले 25 वर्षों में भारत ने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए रूस से परे - विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इजरायल की ओर देखने की कोशिश की है। हालांकि, यह अभी भी भारत रूस को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ गतिरोध में हैं।
- भारत के लिए रूस से उपकरणों और पुर्जों की नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति होना आवश्यक है, और रूस अपनी संवेदनशील रक्षा तकनीकों को चीन के साथ साझा नहीं करे यह भी आवश्यक है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कूटनीतिक चुनौती:

- हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारत को उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ एक नाजुक कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है। भारत ने कूटनीतिक कसौटी पर खरा उतरते हुए रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की, लेकिन युद्ध के शुरुआती हफ़्तों में बुचा नरसंहार की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की और रूसी नेताओं द्वारा जारी परमाणु युद्ध की धमकियों पर चिंता व्यक्त की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई प्रस्तावों में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज़ किया है।
- सितंबर 2022 में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान, उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपनी अंतिम व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक में, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि "यह युद्ध का युग नहीं है" - एक पंक्ति जिसे बाद में नवंबर में G20 के बाली घोषणापत्र में इस्तेमाल किया गया था, और पश्चिमी नेताओं और वार्ताकारों ने रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाला था।

डिजिटल भारत निधि (DBN):

चर्चा में क्यों है?

- दूरसंचार विभाग ने 4 जुलाई को डिजिटल भारत निधि (DBN) को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है।

- 'डिजिटल भारत निधि' पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का स्थान लेगी, जो सभी दूरसंचार निधि परिचालकों पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5 प्रतिशत सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा सृजित निधियों का एक समूह है।

डिजिटल भारत निधि (DBN) क्या है?

- डिजिटल भारत निधि की स्थापना संसद द्वारा पारित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई थी और दिसंबर में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। USOF की स्थापना सार्वभौमिक पहुंच लेवी के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण

क्षेत्रों में किफायती कीमतों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत है।

- विचार यह है कि इस धनराशि का उपयोग दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा, जहां निजी कंपनियां अन्यथा राजस्व पैदा करने वाले बाजार न होने के कारण अपनी सेवाएं देने से परहेज कर सकती हैं।

डिजिटल भारत निधि कैसे काम करेगी?

- दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा।
- सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जिसमें उठाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं, भारत के समेकित कोष में जमा किए जाते हैं। सरकार अपने खर्च भी इसी कोष से करती है।

डिजिटल भारत निधि के पैसे कहां खर्च किये जाएंगे?

- DBN के तहत एकत्रित धन का उपयोग, वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा; दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास को वित्तपोषित किया जाएगा; कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकारी समर्थन का समर्थन किया जाएगा; और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरुआत की जाएगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs:

1. चर्चा में रहे 'S-400 मिसाइल प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह एक लंबी दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है।
   2. यह मिसाइल रक्षा प्रणाली एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans: (b)

2. भारत ने रूस के साथ वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी संधि को, कब एक "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के रूप में अपग्रेड किया था?

(a) 2010 में

(b) 2012 में

(c) 2015 में

(d) 2019 में

Ans: (d)

3. हाल में चर्चा में रहे 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा' से जुड़े महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय उद्देश्यों के लिए किसी विदेशी देश की यह उनकी पहली यात्रा होगी।
2. यह यात्रा रूस को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि दोनों देशों के बीच संबंध बरकरार हैं और भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans: (c)

4. हाल ही में चर्चा में रहे 'डिजिटल भारत निधि' के तहत एकत्रित धन का उपयोग दूरसंचार के किस/किन प्रयोजनों के लिए किए जाएंगे?

(a) वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच और वितरण को बढ़ावा देने के लिए।

(b) कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए।

(c) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरुआत करने के लिए।

(d) उपर्युक्त सभी प्रयोजनों के लिए किए जाएंगे।

Ans: (d)

5. चर्चा में रहे 'डिजिटल भारत निधि' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है।
2. इस निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा लिया गया योगदान सबसे पहले भारत के लोक लेखा कोष में जमा किया जाएगा।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans: (a)